सत्यम् शिवम् सुंदरम्
राष्ट्रिय गुजराती-हिन्दी में प्रकाशित प्रथम पाक्षिक समाचार पत्र
॥ श्री मां जोबनेर माता की कृपा ॥

क्राइम केप

क्राईम केप

R. N. I. No. 70592/98 G-KDA-106/2015-17

"क्राईम केप" અખબારમાં અમદાવાદ ખાતે બ્યુરો ચીફ તરીકે નિમણૂંક કરેલ છે

અમારા "ક્રાઈમ કેપ" અખબારમાં અમદાવાદ સ્થિત ફરીદા એમ. ટીનવાલાની માનદ્ સેવાના હેતુસર બ્યુરો ચીફ તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે. તો આપના વિસ્તારનાં કોઈપણ સમાચાર, જાહેરાત માટે તેમનો સંપર્ક કરવો.

ફરીદા એમ. ટીનવાલા

મો. ૮૪૬૦૩ ૧૬૪૫૨

• वर्ष : 24• अंक : 04 • मूल्य : 2 • पेज : 4 • दिनांक : 1-3-2021 • संपादक : प्रकाश आर. देवल • सह संपादक : हेमल देवल • उप संपादक : देवयानि देवल •

निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र, व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं : पी.एम. मोदी

''उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य हैं । लेकिन यह जरुरी नहीं है कि सरकार इन कंपनियों का स्वामित्व रखे और ईन्हें चलाए ।'' : प्रधान मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गैर रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का जोरदार तरीके से समर्थन करते हुए कहा कि ''व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है ।'' उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सरकारी इकाइयों का निजीकरण करने को प्रतिबद्ध है ।

मोदी ने कहा कि घाटे वाले उपक्रमों को करदाताओं के पैसे के जरिये चलाने से संसाधन बेकार होते हैं । इन संसधनों का इस्तेमाल जन कल्याण योजनाओं पर किया जा सकता हैं ।

मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कम इस्तेमाल या बिना इस्तेमाल वाली संपत्तियों का मद्रिकरण किया जाएगा । इनमें तेल एवं गैस और बिजली क्षेत्र की संपत्तियां हैं । इनके मौद्रिकरण से २.५ लाख करोड़ रुपये के निवेश के अवसर पैदा होंगे ।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य हैं । लेकिन यह जरुरी नहीं है कि सरकार इन कंपनियों का स्वामित्व रखे और इन्हें चलाए ।''

मोदी ने कहा कि, निजी क्षेत्र अपने साथ निवेश, वैश्विक सर्वश्रेष्ठ व्यवहार, बेहतरीन प्रबंधक, प्रबंधन में बदलाव और आधुनिकीकरण लाता हैं । उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बिक्री से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल जन कल्याण योजनाओं मसलन जल और साफ-सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाएगा ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, सरकार चार रणनीतिक क्षेत्रों... परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं परिवहन एवं दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत् के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को प्रतिबद्ध है । उन्होंने कहा कि इनमें सरकार की उपस्थिति को न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।

उन्होंने कहा, व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए । उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आधुनिकीकरण और मौद्रिकरण हैं ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह निवेशकों के मुद्दों को सुलझाने का काम करेगा ।

उन्होंने कहा कि सरकार को विकास पर ध्यान देना है और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जब भी कारोबार करतेहैं, तो घाटा होता है । उन्होंने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, कइयों

(पृष्ठ-२ पर)

गुजरात के ६.५ करोड़ लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं : हार्दिक पटेल

गुजरात में कांग्रेस की हार पर मची रार, नाराज हैं हार्दिक पटेल, बताया क्यों हुई शिकस्त...

नई दिल्ली,

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात निकाय चुनाव में पार्टी की करारी हार पर चुप्पी तोडी है । राज्य के छह नगर निकायों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए पटेल ने खुद की पार्टी को जिम्मेदार बताया है । हार्दिक पटेल ने कहा कि छह नगर निकायों के लिए चुनाव हुए लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी रैली आयोजित नहीं की गई ।

पत्रकारों को दिए इंटरव्यु में हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है । पटेलने यहां तक कह दिया कि पार्टी के कुछ चेहरे उन्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं । पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि, अगर अहमद पटेल जिंदा होते तो बीजेपी को इतनी आसानी से २१९ सीटों का फायदा नहीं लेने देते । हार्दिक पटेल ने आगे कहा कि, कोई बार मैं पार्टी को बताता हूँ कि जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ था तब मैंने सोचा था कि कांग्रेस मेरा उपयोग करेगी । मुझे लगता है कि यहां पर भी मेरा आलाकमान और राज्य पार्टी प्रभारी विफल रहे हैं । हार्दिक पटेल ने कहा कि, मैं एक दिन

(अनुसंधान पृष्ठ-२ पर)

क्राइम केप

मोदी राज में इंसाफ की उम्मीदे इतनी क्षीण हो गई है की... ?

आज मोदी राज में एक २२ साल की लड़की दिशा को जमानत देने के अदालत के फैंसले पर जिस तरह खुशियाँ जाहिर की जा रही है, उसे अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कितने भयग्रस्त समाज में रह रहे है...

एक २२ साल की लड़की को जमानत देने के अदालत के फैंसले पर जिस तरह खुशियाँ जाहिर की जा रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कितने भयग्रस्त समाज में रह रहे हैं। आज के माहौल में इंसाफ कि उम्मीदे इतनी क्षीण हो गई है कि एक हल्की-सी कीरण भी भरी धूप जैसे उजाले का एहसास कराती है। वैसे भी दिशा रवि को जमानत देना अब न छोटी बात है, न मामूली बात है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जिन हालात में दिशा को गिरफ्तार किया गया था, उसमें यही संदेश देने की कोशिश थी की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का कोई साहस न करे। वो तमाम युवा जो खुद को पढा-लिखा मानते हैं, वे अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार के बाजार में अपने लिए ठिकाना तलाश करने में अपनी उर्जा और उत्साह लगाए। सत्ता के काम में मीनमेख निकालने, जनता को जागरुक करने जैसे कामों में अपना समय जाया न करें, अन्यथा उन्हें बाकी का जीवन जेल और अदालतों के बीच गुजारना पड़ सकता है।

दिशा रवि को न केवल गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ट्रोल आर्मी बाकायदा उनके चरित्र हनन में जुट गई। लेकिन दिशा भी शायद हारने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने भरी अदालत में कह दिया था कि अगर किसानों की बात करना गुनाह है तो वह जेल में रहना चाहेगी। उनके जैसे कुठ और उत्साही नौजवान इसी निडरता के कारण अभी जेल में ही है। लेकिन दिशा को अदालत ने जमानत दे दी और इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जो टिप्पणियां की, वे लोकतंत्र के लिहाज से काफी अहम् हैं।पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विगत १३ फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। अदालत में दिशा को पेश करते हुए पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि दिशा रवि टूलकिट गूगल डोक्यूमेंट की एडिटर हैं और इस डोक्युमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है। दिशा पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह, समाज में समुदायों के बीच नफरत फैलाने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में बीते दिने को हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने पुलिस से पूछा था कि यदि में मन्दिर निर्माण के लिए डकैत से संपर्क करुं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं डकैती से जुडा हुआ था और बाद में इस मामले में दिशा को जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा की आवाज के रक्षक होते हैं। उन्हें जेल में सिर्फ इस आधार पर नहीं डाला जा सकता है। एक जाग्रत और मजबूती से अपनी बातों को रखने वाला नागरिक समाज एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान हैं।यह टिप्पणी उन शक्तियों को कड़ा जवाब है, जो सरकार को देश मानते हैं और सरकार से मुखालफत को देशद्रोह बताते हैं। अदालत ने निहारेन्दु दत्त मजुमदार बनाम एम्परर एआईआर मामले के फैंसले के हवाले से कहा, 'विचारों की भिन्नता, अलग-अलग राय, असहमति यहाँ तक अनुपात से अधिक असहमति भी सरकार की नीतियों में वैचारिकता बढ़ाती हैं।' न्यायाधीश राणा ने संविधान के अनुच्छेद १९ की याद दिलाई जिसमें असहमति अधिकार द्रढता से निहित हैं।दिशा को जमानत और अदालत की टिप्पणियां सरकार के साथ-साथ पुलिस, प्रशासन, गोदी मीडिया और उन तमाम लोगों के लिए नसीहत है जो अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल नागरिकों पर करते हैं। पिछले कुछ सालों में राजद्रोह का खौफ जबरदस्त तरीके से जनता के बीच पैदा कर दिया गया हैं। लोगों को अपने एक के लिए आवाज उठाने से हतोत्साहित किया जा रहा है। ताजा उदाहरण किसान आंदोलन ही है, जिसे खत्म करने के लिए सारे पैंतरे आजमाए गए। प्रधानमंत्री से लेकर सत्तारुढ़ पार्टी के तमाम बड़े नेता कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। कुछ समय के लिए जगह-जगह प्रेस कांफ्रेस कर इन कानूनों का लाभ बताने की कोशिष की गई।लेकिन किसान किसी भी तरह इन कानूनों को लाभकारी नहीं मान रहे हैं, बल्कि वे इसमें अपना भविष्य दांव पर लगता देख रहे हैं, तो अब भाजपा नेता ये देख रहे हैं कि इन किसानों को कैसे बहकाया जाए। किसानों को कैसे बहकाया जाए, इसे लेकर एक भाजपा कार्यकर्ता ने गुरुग्राम में आयोजित भाजपा के चिंतन शिविर में सवाल भी पूछ लिया, जिसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडीया पर आई है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि सरकार बहकाने की जगह भरोसा जगाने के मंत्र लोगों की कान में फूंके, ताकि देश और लोकतंत्र दोनों मजबूत हों।

प्रकाश आर. देवल

निजीकरण के...

(पृष्ठ-१ का शुरु...)

को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। इस पैसे का इस्तेमाल कल्याण योजनाओं में किया जा सकता हैं।सरकार का अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बिक्री से १.७५ लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। इन कंपनियों में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कोरपोरेशन ओफ इंडिया, पवन हंस, आईडीआई बैंक और कंटेनर कोरपोरेशन ओफ इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भी आएगा। साथ ही दो सरकारी बैंको ओर एक साधारण बीमा कंपनी की बिक्री की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सुधारों का मकसद यह सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल दक्षता से हो सके।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम देश की मूल्यवान संपत्तियां है और भविष्य में इनके लिए व्यापक संभावना है। उन्होंने कहा कि, निजीकरण अभियान के लिए उचित कीमत खोज को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक व्यवहार को अपनाया जाएगा। मोदी ने कहा, ''कार्यान्वयन भी महत्त्वपूर्ण है। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रक्रियाएँ सही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने को मूल्य खोज और अंशधारकों की मैपिंग के लिए स्पष्ट रुपरेखा होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि,''सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि, रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पडता है। मोदी ने कहा कि, बजट २०२१-२२ में भारत को ऊँची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रुपरेखा बनाई गई हैं। रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं। मोदी ने कहा कि, सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं, ऐसी १०० परिरिंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर २.५ लाख करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे।

भारत को निवेश गंतव्य के रूप में पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, भारत अब एक बाजार, एक कर प्रणाली वाला देश है, कर प्रणाली को सरल बनाया गया है, अनुपालन जटिलताओं में सुधार लाया गया है।

उन्होंने कहा, ''अब भारत की आर्थिक वृद्धि का नया चरण शुरु करने का समय आ गया है।''

Latest On Line my Web. Site all News So
www.crimecap.com
हर बार ! सनसनी खेज समाचार पढे

पाठकों,

यह समाचार पत्र देश के करोडो लोगों की आवाज है और देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक स्थानीय जजो से लेकर सुप्रीम कोर्ट जजों तक, स्थानीय पुलिस अधिकारियों से गृहमंत्री, प्रधानमंत्री व प्रशांसनिक अधिकारियों तक अपराधी आवाज पहुंचाता है। इस आवाज को बुलन्द रखें। आज ही समाचार पत्र के लिए वार्षिक सहयोग ५० रुपए (डाक शुल्क सहित) एवं आर्थिक सहायता भेजने का कष्ट करें।

क्राइम केप
Mo : 9173959559
संपादक : प्रकाश आर. देवल
E-mail : crimecapnews@gmail.com
HO. 209, Aketa Housing Society, Nr. Railway Station At. Ta. Mahemdabad-Dist. Kheda-387130

गुजरात के... (पान-१ का शुरु..)

२५ बैठके करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताएं कि आज से आपको ५०० कि.मी. की पदयात्रा करनी है, मुझे कुछ असाइन तो करें, मैं पार्टी को बार-बार बताता हूँ, मुझे अपना काम दे।हार्दिक पटेल ने कहा कि, अगर पार्टी ने उनको कहा होता कि आपको सूरत में २५ रैलियां करनी है तो नतीजा यह नहीं होता। कांग्रेस पार्टी को आत्म मंथन करना होगा और खुले तौर पर इस बारे में बोलना होगा कि वे कहां असफल रहे या फिर कमजोर थे। हार्दिक ने कहा कि, गुजरात के ६.५ करोड़ लोग बी.जे.पी. को पसंद नहीं करते हैं, चाहे कोई मानता हो या नहीं लेकिन जनता चाहती है कि अगर कांग्रेस लड़ती है तो वे उन्हें वोट देंगे।कांग्रेस आलाकमान ने मांगी रिपोर्ट : वहीं, निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने प्रदेश संगठन की मौजूदा हालत की समीक्षा करने का फैंसला किया है। जनकारी के अनुसार, गुजरात के स्थानिय निकाय चुनावों में कांग्रेस के बेहद चिंताजनक प्रदर्शन को लेकर पार्टी आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस को जवाब तलब करते हुए तत्काल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के प्रभारी को भी आकलन रिपोर्ट दे को कहा गया है। कांग्रेस की राजनीति के जानकारों का मानना है कि, पार्टी नेतृत्व को इस चुनाव में हार से ज्यादा सूरत में आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन अखर रहा है। इसलिए कांग्रेस अब आप को अगले विधानसभा चुनावों में असली रोड़ा मान रही हैं।गौरतलब कि, गुजरात की राजनीति में भी तक दो बड़े दल ही आमने-सामने होते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने सेंध मार कर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी हैं। कांग्रेस का यह भी मानता हैं कि, उनकी पार्टी से बाहर गए लोगो ने ही आप का जनाधार बढ़ाने में मदद की है। बता दें कि, २०१७ में हुए सूबे के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो भाजपा को लगभग सत्ता के पाले से बाहर धकेलती दिख रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने अंतिम दौर में अपने धुआंधार प्रचार की बदौलत भाजपा को वापस सत्ता में ला दिया था। तब भी विधानसभा चुनावों में भाजपा १०० का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और कांग्रेस ने ८० सीटें जीत ली थी।

सरकार की चुप्पी बता रही है कुछ बड़ा होने वाला हैं : राकेश टिकैत

नई दिल्ली,

कैंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को तीन महीने से ज्यादा का सम हो गया है। देश के अन्नदाता अभी भी इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और किसानों ने सरकार की चुप्पी के बाद भी अपना प्रदर्शन जारी रखा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है।राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से कैंद्र सरकार की 'खामोशी' इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रुपरेखा तैयार कर रही है और आने वाले समय में कुछ बडा होने वाला है। सरकार लगातार इस आंदोलन को खत्म करना चाह रही है इसलिए वह हर प्रयत्न कर रही है। अब इतने दिनों से सरकार की चुप्पी से साफ है कि कैंद्र सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं।

दरअसल आज राकेश टिकैत उत्तराखंड में एक महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। इसी महापंचायत में शामिल होने के लि निकले राकेश टिकैत ने पत्रकारों से ये बात कही। बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से राकेश टिकैत ने कहा, '१५-२० दिनों से कैंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला हैं। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रुपरेखा बना रही है।राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि, सरकार चैहे जो भी करे किसान झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, 'समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वह खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर लें।' आपको बता दें कि सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत का दौर थम गया है। सरकार ने अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि किसान प्रस्ताव लेकर आए तब हम बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि, फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे।

राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की रणनीति को लेकर कहा कि, २४ मार्च तक देश में कई जगह महापंचायत की जाएगी। इस महापंचायत के जरिए पूरे देश के किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा।

कैंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को तीन महीने से ज्यादा का समय हो गया है

मोदी सरकार की पिच आमजनों के लिए कमरतोड़ महंगाई से भरी हुई : प्रियंका गांधी

एनपीजी की कीमतों में २५ रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

नई दिल्ली,

एलपीजी गैस की कीमतों में २५ रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट पर कहा, ''पिछले तीन महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर २०० रुपए बढ़े। पेट्रोल, डीजल शतक मारने की तरफ बढ ही चुकी हैं। अर्थव्यवस्था के दोनों छोरों पर खरबपति मित्रों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी सरकार की पिच आमजनों के लिए कमरतोड़ महंगाई से भरी हुई है।''इस महीने, सिर्फ तीन हफ्तों के अंतराल में घरेलू गैस १०० रुपये तक महंगा हो गया है। नवीनतम वृद्धि के बाद, दिल्ली में १४.२ किग्रा के सिलंडर की कीमत को ७९४ रुपये है, जबकि अगले दिन इसकी कीमत ७६९ रुपये थी। दिसंबर में घरेलू सिलेंडरों की कीमत में १०० रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां - इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने तब कीमत में ५० रुपये की वृद्धि की थी। नवीनतम वृद्धि से बीते तीन महीने में सिलेंडर की कीमतों में २०० रुपयें की बढ़ोतरी हो गई हैं।

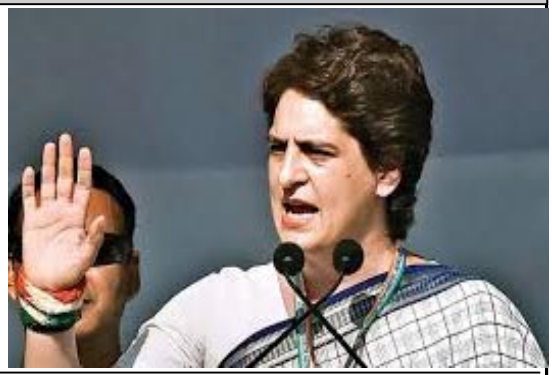

રજીસ્ટ્રેશન ઓફ ન્યુઝ પેપર્સ સેન્ટ્રલ રૂલ્સ ૧૯૫૬ના રૂલ ૮ મુજબ
ક્રાઇમ કેપ સંબંધી માહિતી
(ફોર્મ ૪ : નિયમ-૮ પ્રમાણે)

(૧) પ્રકાશન સ્થળ : ૨૦૯, એકતા હાઉસીંગ સોસાયટી રેલ્વે સ્ટેશન નજીક, મુ.તા.મહેમદાવાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૧૩૦
(૨) પ્રકાશનની મુદત : પાક્ષિક
(૩) મુદ્રકનું નામ અને : પ્રકાશ આર. દેવલ
રાષ્ટ્રિયતા : ભારતીય
સરનામું : ૨૦૯, એકતા હાઉસીંગ સોસાયટી રેલ્વે સ્ટેશન નજીક, મુ.તા.મહેમદાવાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૧૩૦
(૪) પ્રકાશકનું નામ અને : પ્રકાશ આર. દેવલ
રાષ્ટ્રિયતા : ભારતીય
સરનામું : ૨૦૯, એકતા હાઉસીંગ સોસાયટી રેલ્વે સ્ટેશન નજીક, મુ.તા.મહેમદાવાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૧૩૦
(૫) તંત્રીનું નામ : પ્રકાશ આર. દેવલ
રાષ્ટ્રિયતા : ભારતીય
સરનામું : ૨૦૯, એકતા હાઉસીંગ સોસાયટી રેલ્વે સ્ટેશન નજીક, મુ.તા.મહેમદાવાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૧૩૦
(૬) માલિકનું નામ : પ્રકાશ આર. દેવલ
રાષ્ટ્રિયતા : ભારતીય
સરનામું : ૨૦૯, એકતા હાઉસીંગ સોસાયટી રેલ્વે સ્ટેશન નજીક, મુ.તા.મહેમદાવાદ, જી. ખેડા-૩૮૭૧૩૦

હું નીચે સહી કરનાર પ્રકાશ આર. દેવલ જાહેર કરૂં છું કે, ઉપર દર્શાવેલ હકીકતો મારા જાણવા અને માન્યતા મુજબ સાચી છે.

તારીખ : ૧-૩-૨૦૨૧ પ્રકાશ આર. દેવલ
સ્થળ : મહેમદાવાદ માલિક/મુદ્રક/પ્રકાશક/ તંત્રી

દિલ્હી જેવી... (પાન-૪નું ચાલુ...)

આપતા નજરે પડયા હતા. ઘણા વિસ્તારમાં ફુલોનો વરસાદ પણ કરાયો હતો. સુરતમાં પાસની સભાઓ થતી ત્યારે હુ હુ હુ ના નારા યુવાનો લગાવતા હતા. તેવા જ નારા આજે કેજરીવાલના રોડ-શોમાં સાંભળવા મળ્યા હતા.સરથાણા જકાતનાકા પર રોડ-શો સંપન્ન થયા બાદ તક્ષશિલા અગ્નિકાંડમાં ૨૨ નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓએ જીવ ગુમાવ્યો હતો તે સ્થળે કેજરીવાલે જાહેર સભાને સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પચ્ચીસ વર્ષના શાસનમાં ભાજપ સરકાર તમને મફત વિજળી અને પાણી આપી શકી નથી. પણ અમે દિલ્હીમાં આપ્યું છે.તમે આ વાત સાચી નહી માનો પણ દિલ્હીમાં કોઈ તમારા સબંધી રહેતા હોય તે લોકોને પુછીને સાચુ ખોટું સાબિત કરી શકો છે. કેજરીવાલે વધુમાં કહ્યું કે, પાંચ વર્ષ અમને આપો પાછલા પચ્ચીસ વર્ષ તમે ભુલી જશો. પાંચ વર્ષમાં સુરતમાં પણ અમે તમને દિલ્હી જેવી સુવિધા આપી શકીએ છીએ.

ભાજપ શાસકોને આવી સુવિધા આપવાની દાનત નથી એટલે તેઓ તમને કશુ આપતાં નથી. સુરત

મ્યુનિ.માં ૨૭ બેઠકો જીતાડવા બદલ તેમણે સુરતની પ્રજાનો આભાર માની તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ભાજપ અને કોંગ્રેસમાં અનેક સારા માણસો છે પરંતુ તેમની અવગણના કરવામા આવે છે. આવા સારા માણસોને આપમાં પ્રવેશ આપવામા આવશે અને તેમનું સન્મામ કરવામા આવશે.દિલ્હીના મોડલ પર આપ આખા દેશમાં ચૂંટણી લડી રહી છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે , દિલ્હીમાં પહેલીવાર ૨૮ કોર્પોરેટર જીત્યા હતા તેને કારણે વિધાનસભામાં ૬૮ સીટો આવી હતી. તેઓની સારી કામગીરીને કારણે સતત બીજી વાર પણ દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવી છે. આજ મોડલ પર આખા દેશમાં આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી લડી રહી છે.

દેશમાં ભ્રષ્ટ અમલદાર નેતાઓનું ગઠબંધનથી દેશ વિનાશ તરફ જતાં પ્રજામાં ભભૂકતો રોષ !

આપણો આ દેશ આઝાદ થયે ૭૦ વર્ષથી પણ વધુ સમય પસાર થવા પામ્યો છે. આટલાં વર્ષો પછી પણ સરકારો અનેકો કેન્દ્ર અને રાજ્યોમાં આવી અને ગઈ. તમામ સરકારો જનહિત, પ્રજાહિત, દેશહિતની ગુલબાંગો ફાંકી દેશને ગરીબી મુક્ત કરવાની જગ્યાએ હાલ ગરીબ વધુ ગરીબ થવા પામ્યો છે. આજે દેશ વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.

આજની પરિસ્થિતિમાં દેશનાં મોટાભાગમાં સરકારી-અર્ધ સરકારી વિભાગોમાં ભ્રષ્ટાચારનો ભોરીંગ ઘર કરી ગયો છે. પ્રજા પર ભ્રષ્ટ અફસરશાહી, ભ્રષ્ટ પોલીસ તંત્ર અને ભ્રષ્ટ નેતાઓ હવે ગઠબંધન કરી પ્રજાને હડધૂત કરતાં પ્રજાના કાર્યોમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર આચરી પ્રજાને આર્થિક મળતાં લાભોથી વંચિત કરતા હોવાની ઠેર ઠેર ચર્ચા થતી જોવા મળે છે.

દેશમાં ભ્રષ્ટ ગઠબંધન તમામ પ્રજાને મળતાં લાભો પોતે લઈ કાગળો ઉપર ઘોડા દોડાવી તમામ જનહિતના કામો પૂર્ણ થયેલાં બતાવવામાં આવતા હોવાનું જાગૃત પ્રજા પત્રકારોમાં આ અંગે ચર્ચા છે.

મોદી સરકારે કેન્દ્રમાં સત્તાગ્રહણ કર્યા પછીથી જે મોદીજીએ અચાનક નિર્ણયો લીધા તેનાથી દેશ આર્થિક મંદીમાં ધકેલાઈ ગયો અને તે દરમિયાન સરકારના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ, નેતાઓ તથા અમલદારો પ્રજા પ્રત્યે દિવસે દિવસે જડતા દાખવતાં હાલ જોવા મળે છે ? તે કારણે સરકારી વિભાગોમાં પ્રજાને મળતાં લાભો માટે સરકારી ઓફિસોની બહાર સામાન્ય ગરીબ માણસોની લાંબી લાંબી લાઈનો સવારથી સાંજ સુધી જોવા મળે છે. જ્યારે તેમનો નંબર આવે ત્યારે ઘણીવાર તે બારી બર બેઠેલાં કેટલાંક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ ઘણી વખત કાગળો પૂરા હોવા છતાંય તેમાં ખામી દર્શાવી અધુરા હોવાનું જણાવી ગેરમાર્ગે દોરી પ્રજાને અનેકો ધક્કા ખવડાવી પરેશાન અને ત્રસ્ત કરતા જોવા મળે છે. આ લાંબી લાંબી લાઈનો દરમિયાન આ સરકારી કચેરીઓમાં પ્રજામાંથી સાંભળવા મળેલ છે કે, આવી ઓફિસોમાં વચેટીયાઓ રાખવામાં આવે છે. તે પુષ્પમ લઈ પ્રજાના કાર્યો એક કે બે ધક્કા ખવડાવી પૂર્ણ ભાગ્યે જ કરતાહોય છે.

મોદી સરકારે બધું જ હાલ ઓનલાઈન કરી દીધું છે. ડીજીટલ ઈન્ડિયા, મેક ઈન્ડિયા નામ પણ આપ્યું, પણ દેશમાં ભ્રષ્ટ નેતા અમલદારો, ભ્રષ્ટ પોલીસ તંત્ર દેશની પર હાલ સીતમ ગુજારે છે. સરકાર આ બધું જ જાણે છે પણ તમામના ખીસ્સા ગરમ થતાં હોવાથી દેશમાંથી આજે પણ ભ્રષ્ટાચારે ભારે માંઝા મૂકી છે.

જાગૃત પ્રજામાં હાલ ચર્ચા છે કે, મોદી સરકારે બધું જ હાલ ઓનલાઈન કરી દીધું છે. ડીજીટલ ઈન્ડિયા, મેક ઈન્ડિયા નામ પણ આપ્યું, પણ દેશમાં ભ્રષ્ટ નેતા અમલદારો, ભ્રષ્ટ પોલીસ તંત્ર દેશની પર હાલ સીતમ ગુજારે છે. સરકાર આ બધું જ જાણે છે પણ તમામના ખીસ્સા ગરમ થતાં હોવાથી દેશમાંથી આજે પણ ભ્રષ્ટાચારે ભારે માંઝા મૂકી છે. આજે પણ પ્રજા આઝાદ દેશમાં ગુલામ છે અને રહેશે. પણ હવે આ બાબતે પ્રજાએ જ જાગૃત થવું પડશે. નહી તો... !!?

દિલ્હી જેવી સુવિધા માટે પાંચ વર્ષ આપો પાછલા ૨૫ વર્ષ ભૂલી જશો : કેજરીવાલ

સુરત,

સુરતમાં દિલ્હી જેવી સુવિધા જોઈતી હોય તો આમ આદમી પાર્ટીને માત્ર પાંચ વર્ષ આપો અને ભાજપના પાછલા પચ્ચીસ વર્ષ ભુલી જશો. ભાજપ-કોંગ્રેસમાં જેની અવગણના થઈ રહી છે તેવા સારા માણસોને આપમાં જોડાવા માટે મારી અપીલ છે, એમ સુરતમાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ભવ્ય રોડ-શો બાદ યોજાયેલી જાહેરભામાં જણાવ્યું હતું. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આદ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલનો આજે સુરતમાં રોડ-શો યોજાયો હતો. વરાછા માનગઢ ચોક ખાતે સરદાર પટેલની પ્રતિમાને હાર પહેરાવીને રોડ-શોનો આરંભ કરાયો હતો. બરોડા પ્રિસ્ટેજ, કાપોદ્રા, પુણા થઈ રોડ-શો સરથાણા જકાતનાકા પાસે સંપન્ન થયો હતો. તમામ વિસ્તારમા રેલીને આવકાર અપાયો હતો. લોકો રેલી જોવા ટોળે વળતા ઠેર-ઠેર ટ્રાફિકજામ થયો હતો.

ઘણા વિસ્તારોમાં લોકો ધાબા પર ચઢીને રોડ-શોને આવકાર અ

(અનુસંધાન પાન-૩ ઉપર)

- પાટીલના ગઢ સુરતમાં કેજરીવાલનો ભવ્ય રોડ-શો
- પચ્ચીસ વર્ષના શાસનમાં ભાજપ સરકાર તમને મફત વિજળી, પાણી આપી શકી નથી, કારણ કે શાસકોને આપવાની દાનત નથી
- રોડ-શોને લીધે ઠેર-ઠેર ટ્રાફિકજામ, ફુલોનો વરસાદ કરાયો : રોડ-શો જોવા કેટલાક સ્થળે લોકો ધાબા પર ચઢી ગયા

ગુજરાતમાં ૫૮ હજાર બિલ્ડીંગ પાસે ફાયર NOC નથી : સરકાર

અમદાવાદ,

ગુજરાતમાં ૫૮,૨૨૭બિલ્ડીંગ પાસે ફાયર એન.ઓ.સી. (નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ) અને જરૂરી ફાયર સેફ્ટી ઉપકરણો ન હોવાની કેફિયત આપતું સોગંદનામું રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટમાં રજૂ કર્યું છે. આ ઉપરાંત ૩૩,૨૭૪ બિલ્ડીંગો પાસે બી.યુ. પરમિશન ન હોવાની રજૂઆત પણ સરકારે કરી છે, જે પૈકી ૨૫,૯૧૦ બિલ્ડીંગ મ્યુનિસિપાલિટી વિસ્તારોમાં છે. અમદાવાદની શ્રેય હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાથી આઠ કોરોના દર્દીના મોત બાદ ફાયર સેફ્ટીના યોગ્ય અમલ અંગે થયેલી જાહેર હિતની અરજીમાં સરકારે આ વિગતો સોગંદનામા સ્વરૂપે રજૂ કરી છે.રાજ્ય સરકારના અર્બન ડેવલપમેન્ટ અને અર્બન હાઉસિંગ વિભાગ દ્વારા હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલા સોગંદનામામાં જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે કે સમગ્ર રાજ્યમાં ૫૮, ૨૨૭ બિલ્ડીંગો પાસે ફાયર એન.ઓ.સી. નથી અને તેમાં યોગ્ય ફાયર સેફ્ટીની સુવિધાઓ ઈન્સ્ટોલ કરવામાં આવી નથી. અમદાવાદમાં ૧૬,૭૬૧, સુરતમાં ૫૯૨૨, રાજકોટમાં ૫૯૧૭ અને વડોદરામાં ૪૫૮૬ તેમજ નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં ૨૪,૬૭૩ બિલ્ડીંગો પાસે ફાયર એન.ઓ.સી. નથી.આ ઉપરાંત ગુડરાતમા ૩૩,૨૭૪ બિલ્ડીંગ પાસે બી.યુ. પરમિશન પણ નથી. જે પૈકી ૨૫,૯૧૦ બિલ્ડીંગ મ્યુનિસિપાલિટી વિસ્તારોમાં છે. જેમાંથી અમદાવાદમાં ૧૪૮૯ બિલ્ડીંગ, સુરતમાં ૨૩૩૫, ૧૦૦૯ વડોદરમાં અને ૧૬૪૦ બિલ્ડીંગ રાજકોટમાં છે. અમદાવાદની શ્રેય હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાથી આઠ કોરોના દર્દીના મોત બાદ ફાયર સેફ્ટીના યોગ્ય અંમલ અંગે થયેલી રિટમાં આ સોગંદનામું રજૂ કરાયું છે. રિટમાં અરજદારની રજૂઆત છે કે છેલ્લાં બે દાયકાથી થયેલી વિવિધ કાર્યવાહી અને નવાં કાયદાઓ છતાં રાજ્યમાં ફાયર સેફ્ટીના નક્કર અમલનો અભાવ છે.

- ફાયર સેફ્ટીની PILમાં હાઇકોર્ટમાં સરકારનું સોગંદનામું
- અમદાવાદમાં ૧૬,૭૬૧ બિલ્ડીંગ ફાયર શેફ્ટી વગરની અને ૧૪૮૯ બિલ્ડીંગ BU પરમિશન વગરની

OWNER, PRINTER, EDITORS, PUBLISHER : PRAKASH R. DEWAL Printed Hardik Printers, Ahmedabad-22. and Published in • 209, Aketa Housing Society, Nr. Railway Station At. Ta. Mahemdabad-Dist. Kheda-387130 (Responsible for News Edition Under PRB ACT.)